



Published by:

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

#### © Copyright Reserved with the Publishers only.

#### Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

#### Disclaimer/T&C

- 1. For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
- 2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.
- 3. These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.
- In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
- 5. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
- 6. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
- 7. The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
- 8. All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.
- 9. All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.

#### Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

## <u>Content</u>

# भारत का इतिहास (1707–1950 ई.तक) (History of India From C. 1707 to 1950)

Question Paper–June-2023 (Solved)	. 1-2
Question Paper–December-2022 (Solved)	. 1-2
Question Paper–Exam Held in March-2022 (Solved)	1
Sample Question Paper–1 (Solved)	1
Sample Question Paper–2 (Solved)	1

S.No	Chapterwise Reference Book	Page
1.	अठारहवीं सदी का विश्लेषण ( Interpreting the 18th Century )	1
2.	स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव ( Emergence of Independent States )	12
3.	औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना ( Establishment of Colonial Power )	26
4.	1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का प्रसार और सुदृढ़ीकरण ( Expansion and Consolidation of Colonial Power upto 1857 )	37
5.	1857 का विद्रोह ( Revolt of 1857 )	46
6.	औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था : कृषि ( Colonial Economy: Agriculture )	58
7.	औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था : व्यापार एवं उद्योग ( Colonial Economy: Trade and Industry )	71
8.	औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव ( Economic Impact of Colonial Rule )	83

S.No	. Chapterwise Reference Book	Page
9.	उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ( Socio-Religious Movements in the 19th Century )	. 94
10.	राष्ट्रवाद का उद्भव और प्रसार ( Emergence and Growth of Nationalism )	109
11.	महात्मा गांधी के तहत में राष्ट्रवादी आंदोलन ( Nationalist Movement under Mahatma Gandhi )	123
12.	साम्प्रदायिकता : उद्भव, प्रसार और भारत का विभाजन ( Communalism: Genesis, Growth and Partition of India )	137
13.	स्वतंत्रता का आगमन : संविधान सभा, गणतंत्र की स्थापना ( Advent of Freedom: Constituent Assembly, Establishment of Republic )	149



## **QUESTION PAPER**

June – 2023

(Solved)

भारत का इतिहास ( 1707-1950 ई. तक ) 🛛 🖪

(History of India From C. 1707 to 1950)

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। भाग - I प्राप्त 1 वंग्राल में प्रथानी वन्त्रोवान लाग करने के मीले शैली से प्रेरित था। अधिकतर प्रशासनिक सुधारों की प्रेरणा अहमदनग

प्रश्न 1. बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-6, पृष्ठ-64, प्रश्न 4

प्रश्न 2. ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-3, पृष्ठ–77, 'बंगाल की ब्रिटिश विजय : 1757-1765'

प्रश्न 3. मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय–2, पृष्ठ–12, 'मैसूर का उत्थान', 'मैसूर में युद्ध और सैन्यीकरण की भूमिका', पृष्ठ–13, 'मैसूर का प्रशासन', 'मैसूर के वित्तीय संसाधन'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(i) अट्ठारहवीं शताब्दी सम्बन्धी वाद-विवाद

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-1, पृष्ठ-1, अठारहवीं शताब्दी संबंधी वाद-विवाद'

(ii) साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय–4, पृष्ठ–39, 'साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण'

(iii) राजस्व संस्थाएँ

समय : 3 घण्टे ।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-64, प्रश्न 5

(iv) मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था

उत्तर–मराठा राज्य ने हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया और फारसी की जगह मराठी को राजभाषा का दर्जा दिया। उन्होंने राजकीय प्रयोग हेतु 'राज व्याकरण कोश' नाम से स्वयं का एक शब्दकोश निर्मित किया। मराठा साम्राज्य का अध्ययन निम्नलिखित तीन शीर्षकों के तहत किया जा सकता है–केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन।

**केंद्रीय प्रशासन**-इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा समर्थ प्रशासनिक प्रणाली हेतु की गयी थी, जो कि मुख्यत: दक्कन की प्रशासनिक शैली से प्रेरित था। अधिकतर प्रशासनिक सुधारों की प्रेरणा अहमदनगर में मलिक अम्बर द्वारा किये प्रशासनिक सुधारों से मिली थी। राजा सर्वोच्च पदाधिकारी था, जिसकी सहायता 'अष्टप्रधान' नाम से जाना जाने वाला आठ मंत्रियों का समूह करता था।

अष्टप्रधान–

**पेशवा या प्रधानमंत्री**-यह सामान्य प्रशासन की देख-रेख करता था।

अमात्य या मजूमदार–यह लेखा प्रमुख था जो बाद में राजस्व एवं वित्त मंत्री बन गया।

**सचिव या शुरू-नवीस**-इसे चिटनिस भी कहा जाता था और ये राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था।

**सुमंत या दबीर**–यह राजकीय समारोहों और विदेश मामलों का प्रमुख मंत्री था।

सेनापति या सर-ए-नौबत–यह सेना प्रमुख था जो सैन्य भर्ती प्रशिक्षण एवं अनुशासन की देख-रेख करता था।

मंत्री या वाकिया-नवीस–यह आसूचना, राजा की निजी सुरक्षा एवं अन्य गृह-कार्यों का प्रमुख था।

**न्यायाधीश**–यह न्याय प्रशासन का प्रमुख था।

पंडितराव–यह राज्य के धर्मार्थ एवं धार्मिक कार्यों का प्रमुख था और जनता के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करता था।

पेशवा, मंत्री एवं सचिव नाम के तीन मंत्रियों को अपने विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त बड़े प्रान्तों के प्रभारी का दायित्व भी सौंपा जाता था। न्यायाधीश और पंडितराव को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को अपने असैनिक दायित्वों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी होती थी। मंत्री को निम्नलिखित आठ मुंशियों/लिपिकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता था–

दीवान-सचिव,

**मजुमदार–**लेखा परीक्षक एवं लेखाकार, फडनीस–उप-लेखा परीक्षक, सबनीस या दफ्तरदार–दफ्तर का प्रमुख,

(B.H.I.C.-134)

। अधिकतम अंक : 100

2 / NEERAJ : भारत का इतिहास ( 1707-1950 ई. तक ) (JUNE-2023)

चिटनिस–पत्राचार लिपिक, जामदार–कोषाधिकारी, पोतनीस–रोकड़ अधिकारी,

कारखानीस-प्रतिनिधि।

शिवाजी ने अपने संपूर्ण राज्य को चार प्रान्तों में विभक्त किया और प्रत्येक प्रान्त एक राज-प्रतिनिधि (वायसराय) के अधीन होता था। उसने प्रान्तों (सूबों) को पुन: परगनों और तालुकों में विभक्त किया। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया पाटिल (पटेल) होता था।

राजस्व प्रशासन–शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसकी जगह रैय्यतवारी प्रणाली लागू की और देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी नाम से प्रसिद्ध वंशानुगत राजस्व कर्मचारियों की स्थिति में परिवर्तन किया। शिवाजी ने मिरासदारों, जिनके पास भूमि के वंशानुगत अधिकार थे, पर कड़ी निगरानी रखी। राजस्व प्रणाली मालिक अम्बर की काठी प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली के अनुसार भूमि के प्रत्येक भाग की माप छड़ी या काठी से की जाती थी। चौथ और सरदेशमुखी उनकी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का चौथाई भाग था, जिसे गैर-मराठा क्षेत्रों से, मराठा आक्रमण से बचने के एवज में, मराठों द्वारा वसूला जाता था। सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था, जो आय का दस प्रतिशत होता था और राज्य से बाहर स्थित क्षेत्रों से वसूला जाता था।

सैन्य प्रशासन-शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना तैयार की। सामान्य सैनिकों को नकद भुगतान किया जाता था, लेकिन बड़े-बड़े सरदारों और सेनापति को भुगतान जागीर अनुदान (सरंजाम या मोकासा) के रूप में किया जाता था। सेना में पैदल सेना (जैसे-मावली सैनिक), घुड़सवार (जैसे-बारगीर एवं सिलेदार), साजो-सामान ढोने वाले और नौसेना शामिल थी।

सैन्य अधिकारी/कर्मचारी-

**सर-ए-नौबत ( सेनापति )**–सेना प्रमुख, **किलादार**–किलों का अधिकारी, **पायक**–पैदल सैनिक, **नायक–**पैदल सेना की एक टुकड़ी का प्रमुख, **हवलदार–**पांच नायकों का प्रमुख, **जुमलादार**-पांच हवलदारों का प्रमुख,

**घुराव-**बंदूकों से लदी नाव,

गल्लिवत-40-50 खेवैयों द्वारा खेने वाली नाव।

मराठा राज्य, जहां त्वरित सैन्य अभियान महत्वपूर्ण थे, की नीतियों के निर्धारण में सेना एक प्रभावी उपकरण थी। केवल वर्षा ऋतु में सेना आराम करती थी अन्यथा पूरे साल अभियानों में व्यस्त रहती थी। पिंडारियों को सेना के साथ जाने की अनुमति थी, जिन्हें "पाल-पट्टी", जो कि युद्ध में लूटे गए माल का 25 प्रतिशत थी, को वसुलने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

#### भाग - II

प्रश्न 5. राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-10, पृष्ठ-109, 'मध्यम वर्ग की चेतना का उदय', 'राष्ट्रवाद की प्रारंभिक साहित्यिक और संगठनात्मक अभिव्यक्ति' तथा पृष्ठ-112, प्रश्न 1

प्रश्न 6. 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-100, प्रश्न 4

प्रश्न 7. उत्तर-औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने प्रभावित किया, चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-151, 'स्वतंत्रता के बाद की राज्य व्यवस्था पर राष्ट्रवादी विरासत का प्रमुख' तथा पृष्ठ-154, प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

*(i)* कृषि का वाणिज्यीकरण

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-8, पृष्ठ-88, प्रश्न 5

(ii) गरम दल का सैद्धान्तिक आधार

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-10, पृष्ठ-11, 'गरम दल (उग्र दल) का सैद्धांतिक आधार'

*(iii*) हिन्द स्वराज

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-11, पृष्ठ-129, 'हिंद स्वराज का विचार'

(iv) बीसवीं शताब्दी में साम्प्रदायिकता

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय–12, पृष्ठ–138, 'बीसवीं शताब्दी में साम्प्रदायिकता'



# भारत का इतिहास ( 1707-1950 ई. तक) (History of India From C. 1707 to 1950)

## अठारहवीं सदी की व्याख्या (Interpreting the 18th Century)

## परिचय

मुगल साम्राज्य का वर्चस्व भारत के काफी बड़े भू-भाग पर लगभग तीन शताब्दियों तक बना रहा। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई। मुगल साम्राज्य की राजनैतिक सीमाएँ कम नहीं हुईं, बल्कि अकबर और शाहजहां ने पूरी मेहनत से प्रशासनिक संरचना की थी, वो भी चरमरा गई। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और साथ ही साम्राज्य के सभी भागों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया।

इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया को लेकर काफी बहस चली है। विद्वानों के बीच सबसे ज्यादा मतभेद मुगल इतिहास के इसी पक्ष के लिए है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को दो मुख्य हिस्सों मुगल केन्द्रित दृष्टिकोण और क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण में बांटा जा सकता है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण विद्वान स्वयं साम्राज्य की संरचना और कार्यपद्धति में ढूंढ़ते हैं। इसे मुगल केंद्रित दृष्टिकोण कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण विद्वान स्वयं साम्राज्य की संरचना और कार्यपद्धति में ढूंढ़ते हैं। इसे मुगल केंद्रित दूष्टिकोण कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को स्थानीय समस्याओं और साम्राज्य के विभिन्न भागों में फैली अव्यवस्थाओं में ढूंढा जाता है। इसे क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण कह सकते हैं।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### अठारहवीं शताब्दी : प्रमुख विशेषताएँ

इस समयवधि की प्रमुख विशेषताओं को समझने के लिए इस दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। प्रथम मुख्य परिवर्तन मुगल साम्राज्य का विभाजन है जिससे यह क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में बॅंट गया। दूसरा यह कि इतिहासकारों ने अठारहवीं शताब्दी के प्रभावों को समझने के लिए इसका एक 'दीर्घकालीन' शताब्दी के रूप में अध्ययन किया है। आधुनिक विश्लेषण के अनुसार, इस शताब्दी की राजनीतिक गतिशीलता का आधार 1680 के आस-पास मुगल साम्राज्य के विखंडन में निहित है। एक अन्य तीसरा परिप्रेक्ष्य है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मध्य सम्बन्धों का अवलोकन करता है। प्रारंभिक आधुनिक व्यापार के यूरोपीयकरण ने अठारहवीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर प्रभाव डाला और इस माध्यम से भारत में काफी धन आया। अठारहवीं शताब्दी में सत्रहवीं शताब्दी की तुलना में विश्वव्यापी आर्थिक विस्तार हुआ और भारत के समुद्री व्यापार में इस समय असाधारण रूप से समृद्धि आयी। अत: अठारहवीं शताब्दी को आर्थिक पृथकीकरण का युग मानने वाला विचार सही नहीं है।

### अठारहवीं शताब्दी संबंधी वाद-विवाद

कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आने के कारण अठारहवीं शताब्दी पर इतिहासकारों द्वारा लगभग प्रत्येक विषय पर विभिन्न व्याख्याएँ दी गयी हैं। इस शताब्दी को दो भागों में बांटा गया है–1750 तक तथा 1750 के बाद। 1750 तक के समय को वाद-विवाद के परिप्रेक्ष्य से मुख्यतया दो भिन्न दृष्टिकोणों में वर्गीकृत किया गया है–साम्राज्य–केन्द्रित और क्षेत्र केन्द्रित दृष्टिकोण। इसी प्रकार 1750 के बाद वाले वाद–विवाद को भारतीयता और यूरोपीयकरण के दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

साम्राज्य-केन्द्रित दूष्टिकोण अन्तर्गत कुछ इतिहासकार मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं की केन्द्रीयता और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारक मानते हैं। इसके अनुसार साम्राज्य के पतन के विध्वंसक परिणाम हुए, जिससे देश में राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आ गई। हाल की व्याख्याओं में इस पतन को संरचना के ह्वास के रूप में देखा गया है। लेकिन इससे कोई सकारात्मक विचार नहीं उभर पाया। क्षेत्रीय राज्यों पर प्राय: यह आरोप लगता है कि वे अपने स्वतंत्र राज्य को एक मुगल सुबे से

## www.neerajbooks.com

#### 2 / NEERAJ : भारत का इतिहास ( 1707-1950 ई. तक )

अधिक विकसित नहीं कर पाए। साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करने वाले साम्राज्य केन्द्रित विचार के विपरीत क्षेत्र-केन्द्रित विचार साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले सामाजिक समूहों को केन्द्र में रखते हैं। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलत: बदल दिया गया जिससे एक स्तर पर बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। दूसरे स्तर पर मुगलों के विरोध के परिणामस्वरूप मराठा और सिख जैसी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। उनके राजनीतिक तंत्र का आधार मुगल प्रशासनिक पद्धतियाँ ही बनी। इस परिवर्तित क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों ने मुगल कुलीन-वर्ग को क्षेत्रों में अपनी शक्ति को और मजबूत करके कृषि पर मालिकाना अधिकार स्थापित किया तथा राजस्व को वसूलने का अधिकार भी प्राप्त किया। आने वाले समय में यह उनकी पुश्तैनी जायदाद बन गई। क्षेत्रों में व्यापारिक विकास से इनकी स्थिति और मजबूत हुई।

1750 के बाद की स्थिति के संदर्भ में यूरोपवादी दृष्टिकोण विजयी, विस्तारवादी के प्रभुत्व को प्रमुखता देते हैं, जिसके अनुसार तत्कालीन भारत में अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी और अत: वह यूरोपीय शक्ति के सम्मुख हार गया। यह भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है। इस राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुसार, अठारहवीं शताब्दी में भारत में फैली अराजकता के कारण यह राष्ट्र एक विदेशी शक्ति के अधीन होकर उसका उपनिवेश बन गया। परम्परागत मार्क्सवादी विचारधारा अंग्रेजी शासन की भर्त्सना करते हुए इसे ही अठारहवीं शताब्दी के सामन्तवादी विघटन के अन्त का मूल मानती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी शासन निरन्तर लाभ, वस्तुओं तथा बाजारों की खोज में था और जिसका कोई प्रगतिशील पहलू नहीं था। इतिहासकारों के दृष्टिकोण में कुछ सामान्य मान्यताएँ इस प्रकार हैं–

- व्यवस्था और स्थिरता एक बड़ी अखिल-भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ही हो सकती है और चूँकि यह स्थिरता अठारहवीं शताब्दी में समाप्त हो गई, इसलिए इस काल में अव्यवस्था, अराजकता और पतन आया।
- इस शताब्दी में राजनीतिक विच्छिन्नता आई।
- अंग्रेजी शासन एक मूलभूत वियोजन था, जो विदेशी और अनजान आधिपत्य पर आधारित था तथा यह भारतीय अधिशासन या संस्कृति की परम्पराओं से बहुत दूर था।

दूसरी ओर, भारतवादी परिप्रेक्ष्य उपनिवेशवाद के इस संक्रमण– काल को विभेदक मानते हुए अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को विजय और अधीनीकरण का एकतरफा प्रक्रम न मानकर भारत के साथ यूरोप (विशेषत: अंग्रेजों का) की लम्बे समय तक सम्बद्धता पर बल देते हैं। यह विचारधारा इस मत पर बल देती है कि किस प्रकार से भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को बढावा दिया। भारतवादी दुष्टिकोण अठारहवीं शताब्दी को मात्र

अराजकता से भरपुर परिस्थितियों का समर्थन नहीं करता। उनके मतानुसार मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। इस मत के अनुसार अठारहवीं शताब्दी में भी भारत की व्यापारिक और सैन्य-कुशलता बनी रही और कम्पनी ने इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। भारत में अंग्रेजी शासन के निर्धारण में महानगरीय स्वार्थों के साथ-साथ भारतीय कारकों का भी योगदान था। अंग्रेजी शासन भारतीय शासन प्रणाली के आदर्शों, कृषि-व्यापारिक प्रबंधों और मानव संसाधनों की दक्षता पर आधारित था, परन्तु उसने उसे अपने उद्देश्य के अनुरूप बना लिया। उनके तर्क के अनुसार, भारतवादी दृष्टिकोण के मतानुसार, अठारहवीं शताब्दी अवरुद्धता के बजाय निरन्तरता को दर्शाती थी, जिसमें पहले से चली आ रही संस्थाएँ और संचनाएँ बनी रहीं। लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया और चारों ओर व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ। इस मत के समर्थक 'कैम्ब्रिज स्कूल' से सम्बंधित हैं। इन्हें 'संशोधनवादी' इतिहासकार की संज्ञा दी गई है।

### मुगल साम्राज्य, उसका पतन और अठारहवीं शताब्दी का प्रारंभ

आधुनिक इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य की अवनति के सन्दर्भ में नैतिक भ्रष्टता का सिद्धान्त, कमजोर शासन और साम्प्रदायिक नीति की रूढ़िवादी विचारधारा का विशेष समर्थन नहीं किया है। उनके अनुसार उस समय घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था। इरफान हबीब ने जागीरदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है।

इरफान हबीब ने मुगलों द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व की व्यवस्था मे दोष को परिलक्षित किया। साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी सेनाओं के रख-रखाव के लिए राजस्व की दर ऊँची रखी जाने लगी और अल्यधिक वसूली से कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। साथ ही कुलीनों के जागीर में स्थानांतरण से भी शोषण का दौर बढ़ चला। अब किसानों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया तथा कई किसान खेत छोड़कर भाग गए। इस काल में साम्राज्य के राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे में क्षीणता आई।

सतीश चन्द्र के अनुसार, साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण राज्य के अधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने की असमर्थता था जिसने आपसी गुटबाजी में तीव्र संघर्ष को जन्म दिया।

सतीशचंद्र ने अपनी पुस्तक 'पार्टिज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, 1707-40' में मुगल साम्राज्य की प्रकृति और पतन पर गंभीर छानबीन की है। मुगल पदानुक्रम व्यवस्था में मनसबदारों को जागीरें दी जाती थीं, जिन्हें सैनिक रखने की भी अनुमति थी। अत: मुगलों की राजस्व वसूली के मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता भी ये जागीर ही थे। सतीश चन्द्र के अनुसार औरंगजेब अपने अंतिम वर्षों में इस व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ।

## www.neerajbooks.com

## www.neerajbooks.com

#### अठारहवीं सदी की व्याख्या / 3

इनका प्रभावशाली ढंग से समाधान नहीं कर पाए। जैसे सरकार भू-राजस्व निर्धारण (जमा) और वास्तविक कर-वसूली (हासिल) में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाई। इसी प्रकार संरचनात्मक असमर्थता के कारण वह स्थानीय विशिष्ट वर्ग और क्षेत्रीय नायकों के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाई। दर-दर तक फैले हए छोटे-छोटे जमींदारों के साथ कोई व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित न कर पाने की अक्षमता ने समस्याओं को ओर बढाया। ये सभी दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याएं थीं। सरकार द्वारा साम्राज्य में , जिसमें दोनों की सम्मति हो. ने मसावत और जोरतलाब (ऐसे क्षेत्र जो हमेशा विद्रोही रहे हों) इलाके सर-ए-हासिल इलाकों के साथ-साथ थे। ये सभी दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याएं थीं। अल्पकालिक समस्याओं में दक्खन का संकट, उत्तरी भारत में गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में चले आ रहे जाट और मेवातियों के दीर्घकालीन विरोधी-आन्दोलन और पंजाब में सिखों के विरोध आदि सम्मिलित हैं। पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, लेकिन पर्याप्त वसुली न होने के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ बढी। इन अल्पकालिक संकटों ने पूर्व में उत्पन्न राजकीय अनिवार्यताओं और स्थानीय अनिवार्यताओं के मध्य दीर्घकालिक संघर्षों में और भी वृद्धि की जिससे साम्राज्य का ह्वास हुआ।

तात्पर्य यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करते समय केन्द्र और स्थानीय क्षेत्रों के निरन्तर बदलते हुए, समझौतावादी संबंधों और कुलीन-वर्ग तथा स्थानीय सरदारों के बीच निरन्तर तनावों का अध्ययन आवश्यक है। साम्राज्य द्वारा केन्द्रीयकरण के प्रयास से क्षेत्रीय समूहों को उतना ही अधिक लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने केन्द्रीयकरण की इस प्रक्रिया को अपनाकर लाभ उठाया। साम्राज्य ने जैसे-जैसे राजस्व व्यवस्था द्वारा धन संचय किया, स्थानीय समूहों द्वारा उसके अतिक्रमण की प्रवृत्ति रही, जिसने आपसी तनाव बढ़ाया। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव का सामाजिक-

## आर्थिक संदर्भ

साम्राज्य के क्षेत्र-केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भी उसके पतन के कारक सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, आंद्रे विंक ने 'फितना' के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए माना है कि राज्य व्यवस्था निरन्तर गुटबंदी के कारण चरमरा रही थी और केन्द्रीकरण से लगातार दूर जा रही थीं। स्टिफन ब्लेक ने इस सन्दर्भ में मुगल व्यवस्था की पैतृक-नौकरशाही की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके अनुसार, मुगल शासक सदैव व्यक्तिगत (पैतृक) और अत्यंत सैन्यीकृत और केन्द्रीय पहलुओं में संतुलन रखने के प्रयत्न में ही लगे रहे, जो धीरे-धीरे असंगत होता जा रहा था। एम.एन. पियर्सन ने भी माना कि मुगल शासक एक पैतृक, अत्यधिक व्यक्तिगत शासन और अपनी सैनिक आकांक्षाओं के बीच की दरार को लांघ नहीं पाए। अपने सेना को कामयाब बनाने के प्रयत्न में वे एक स्वतंत्र सैन्य नौकरशाही प्रथा की स्थापना नहीं कर पाए। मुज़फ्फर

एम. अजहर अली के अनुसार दक्कन और मराठा राज्यों में साम्राज्य विस्तार से कुलीनों की संख्या में वृद्धि हुई तथा जागीर व्यवस्था संकट में आ गई।

प्रो. एस. नुरूल ने मुगल प्रशासन को पिरामिडीय आकार दिया है तथा कृषि को आधारभूत माना है। मुगलों के पतन के साथ जागीरों पर दबाव पड़ने लगा तथा कृषि व्यवस्था चरमरा गई।

अत: जागीरदारी संकट के कमजोर पड़ने तथा उससे मुल कोष पर प्रभाव पड़ने से मुगल साम्राज्य के पतन में तीव्रता आ गई।

अथर अली ने मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जागीरों की अत्यधिक कमी को माना है। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के परिणामस्वरूप भू-आवंटन के आकांक्षियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे जागीर व्यवस्था चरमरा गई।

जे.एफ. रिचर्ड्स ने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर नए दृष्टिकोण से विचार किया तथा बेजागीरी (अनुपस्थित जागीरी) को मुगलों के पतन का प्रधान कारण माना हैं। औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन में साम्राज्य के अधिग्रहण से साम्राज्य की आमदनी में तो वृद्धि हुई, किन्तु कुलीनों की संख्या में वृद्धि ने जागीरदारी संकट पैदा कर कर दिया। युद्ध के खर्चे की वसूली के लिए जागीरों को खालसा भूमि में परिणत कर दिया गया, जिसके कारण पायबाकी जागीरों (जो भूमि जागीर के रूप में देने के लिए सुरक्षित रखी जाती थी) की कमी हो गई। यह समस्या बेजागीरी से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि प्रशासनिक थी। सतीश चन्द्र ने 1980 के शोध में जागीरदारी और बेजागीरी को अलग किया है तथा जागीर व्यवस्था और आय में संकट इसके सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण उत्पन्न हुआ है, स्वीकार किया।

मार्शल हॉगसन के एक रोचक तर्क के अनुसार, ऑटोमन, सफविद और मुगल, तीनों मुसलमान साम्राज्य की सफलता और पतन का मुख्य कारण गोला-बारूद का सही प्रयोग था, क्योंकि इसके कारण उन्होंने पश्चिमी गोलार्द्ध में युद्ध के क्षेत्र में बदलती हुई नई तकनीकियों को नहीं अपनाया। इक्तिदार आलम खान ने भी माना कि बन्दूक, तोप और गोला-बारूद्ध ने जहाँ साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया वहीं शक्तिशाली प्रजा ने उनका प्रयोग अपने को सशस्त्र करने के लिए और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया। स्टुअर्ट गॉर्डन ने भी प्रमाणित किया कि अठारहवीं शताब्दी में मराठाओं ने एक बहुत बड़े और पंचमेल सैन्य श्रमिक बाजार का उपयोग किया जिसमें यूरोपीय भी शामिल थे। अत: मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालिक दोनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण के अनुसार मुगल साम्राज्य ने शक्ति के केन्द्रीकरण के लिए कई संस्थाओं की नींव रखी. लेकिन संकट आने पर वे

## www.neerajbooks.com

#### 4 / NEERAJ : भारत का इतिहास ( 1707-1950 ई. तक )

आलम ने दिखाया कि स्थानीय भद्र और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग इस राजकीय प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी स्थिति को और मजबूत बनाता रहा। लेकिन इन वर्गों की प्रकृति सब जगह सामान नहीं थी। अवध के लोग समाज के ऊँचे वर्ग (अशरफ) से संबंधित थे जबकि बाकी स्थानों पर कुछ निम्न श्रेणी के तत्व थे जैसे पंजाब में जाट, किसान, या बंगाल में स्थित सदगोप जमींदारी आदि। महाजन और व्यापारी भी इस श्रेणी में सम्मिलित थे, क्योंकि वे कुछ पैसे देकर लागत की जिम्मेदारी लेते थे। अत: उस समय की व्यवस्था बहु-ध्रुवीय तनाव में थी। सी.ए. बेली ने इस संकट का कारण कई तरह के सैन्य, व्यापारिक और राजनीतिक ठेकेदार के नाम से संबोधित होने वाले ऐसे गुटों के उदय को माना है, जिन्होंने एकजुट होकर मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए व्यापार और उत्पादन का फायदा उठाया। इस उदय का अर्थ पतन नहीं है। इसका अर्थ है कि सामाजिक विस्थापन के साथ नवीन संस्थाओं का उदय हुआ।

अठारहवीं शताब्दी की राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में तीन प्रकार की शासन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रथम पहले से चली आ रही मुगल शासन प्रणालियों की प्रतिकृति. जिसमें अवध और बंगाल के नवाब के मुगल सूबेदार थे, जो उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में इन प्रान्तों पर राज कर रहे थे और इन्होंने मुगल प्रथाओं और रीतियों को ही अपनाया। दुसरी श्रेणी में मराठा, जाट और सिख राज्य आते थे। इनकी उत्पत्ति मुगल साम्राज्य से हटकर हुई थी अतः इनकी प्रकृति अलग थी। इन राज्यों ने सुदुढीकरण के लिए नए राजनैतिक और प्रशासनिक तंत्रों की स्थापना की। ये राज्य मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से चुनौती देते थे। तीसरी श्रेणी में सम्मिलित संरचनाएँ राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण थीं। इसमें मुसलमान तथा हिन्दु और आदिवासियों के कई स्थानीय प्रभाव क्षेत्र आते थे जो अर्ध-स्वाधीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित थे। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र से हारने के पश्चात् राजपूत वंशों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में अवध तक विजय प्राप्त करके. प्रवासन और व्यवस्थापन द्वारा छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना की।

अफगान सरदारों ने रोहिलखण्ड और भोपाल पर विजय प्राप्त कर, ठेके पर राजस्व और दक्षिण-पश्चिम सीमावर्ती इलाकों के साथ व्यापार द्वारा अपने राज्यों की स्थापना की। बुर्दवान और कासिम बाजार के जमींदारों ने क्रमश: बनारस राज और बंगाल में राजस्व के ठेके (इजारा) और व्यापार द्वारा अपने राज्यों से संगठित किया। उत्तर-पूर्व सीमा में हिन्दू वंशी आहोम राजाओं ने मुगल साम्राज्य को 1680 के आस-पास बढ़ने से रोका और अंग्रेजों के आक्रमण तक असम को स्वाधीन रखा। 1760 के लगभग दक्षिण में मैसूर के आस-पास राजतंत्र का केन्द्रीयकरण हुआ। डेविड लड्डन का कहना है कि उससे पहले की स्थिति यह थी कि तेलगुभाषी नायकों ने छोटे-छोटे राज्य बना रखे थे। वहीं कई पलायाक्करार या पोलिगार थे जिन्होंने नायकों के क्षेत्रों में अपने छोटे क्षेत्र बनाए जो मंदिरों पर आधारित थे और जिनका अत्यधिक मात्रा में सैन्यीकरण हुआ। मालाबार तट पर तटवर्ती राज्यों और जमींदारों घरानों में सन्धिपूर्ण रिश्ता था जो व्यापार, भूमि और श्रम से प्राप्त होने वाले लाभ को पारस्परिक रूप में बाँट लेते थे। मैसूर के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में राजतंत्र का प्रारम्भ हैदर अली और टीप सुल्तान के द्वारा किया गया।

#### बोध प्रश्न

प्रश्न 1. अठारहवीं शताब्दी में देखे गए दो संक्रमण क्या हैं?

**उत्तर–**अठारहवीं शताब्दी में देखे गए दो संक्रमण इस प्रकार है–

- प्रथम, मुगल साम्राज्य विघटित होकर क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में विभक्त हो गया, जो इस परिवर्तन का मुख्य कारण माना गया है। यह परिवर्तन मात्र क्षेत्रीय और सामाजिक गुटों में राजनीतिक शक्ति में पुनर्वितरण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक था। इस शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी (1757) और बक्सर (1763) के युद्ध में जीतने के पश्चात् राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने में सफल हुई, जो केवल भारत से व्यवसाय कर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्मित हुई थी। इससे सामुद्रिक व्यापार संगठन में परिवर्तन आया। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य और व्यापारिक प्रभाव को बढाया।
- दूसरा यह कि इतिहासकारों ने अठारहवीं शताब्दी के प्रभावों को समझने के लिए इसका एक 'दीर्घकालीन' शताब्दी के रूप में अध्ययन किया है। आधुनिक विचारों के अनुसार इस शताब्दी में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल को 1680 के आस-पास हुए मुगल साम्राज्य के विखंडन से जोडा जाता है। 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। 1750 से कम्पनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक सम्बन्धों की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है, जो 1820 तक चलता रहता है। इसके अंतर्गत प्राय: सभी स्वदेशी राज्यों का अंग्रेज शासित प्रदेशों में विलय सम्मिलित है। सहायक संधि के अंतर्गत सभी राज्य अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गए तथा कुछ इनके मित्र बन गए। इस प्रकार राजनीतिक महत्व की दुष्टि से, अठारहवीं शताब्दी, सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों और उन्नीसवीं शताब्दी के पहले तीन दशकों को अपने में आत्म-सात करती है। आर्थिक

## www.neerajbooks.com